RAJYA SABHA

Thursday, the 13th May, 1993/23 Vaisakha, 1915 (Saka)

The House met at eleven of the clock, *Mr. Chairman* in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*241. [The questioner (Shri Abdul Samad Siddiqui) was absent. For answer, vide col. . . . *infra*]

Economy in construction works in the army

RI DIGVIJAY SINGH: Will MINISTER be pleased to

whether the Armed Forces have ated any measures for bringing about economy in the cost of Civil/Marine Construction Works which run into several thousands crores of rupees;

(b) if so, what are the steps initiated and the progress made in this regard;

(c) whether any new or alternate Competitive Construction technologies r materials have been identified by the Forces; and

(d) if so, what steps have been taken by the Armed Forces to adopt these technologies and materials?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

A number of measures have been implemented by that Ministry Engineer Service (MES) to introduce economies in construction costs.

Through inter-action with research agencies such as the Central Buildings Research Institute (CBRI), the National Building Organisation (NBO), the Central Road Research Institute (CRRI), the Structural Engineering Research Centre (SERC), and other institutions such as the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) the MES has identified certain cost saving techniques and new building materials for incorporation in defence construction. Besides yielding reductions in cost, such measures also reduce construction times.

Some of the important measures relating to building construction have been:

(i) The introduction of limit state method of design, and use of high strength deformed steel bars.

(ii) The use of pre-fabricated concrete members for roof and floor slabs.

(iii) Use of steel members in place of timber in building works.

As regards marine construction, mention may be made of the following innovations:

(i) The use of monoliths for dock-yard walls as against the conventional technique requiring coffer dams.

(ii) Incorporation of air pockets in flap gates, thus reducing the quantity of steel needed in conventional design.

(iii) Use of suspended floors, supported on filter media, as against the conventional technique of providing mass concrete flooring.

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति जी, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उस जवाब से, मेरे सवाल को ऐसा लगता है कि उन्होंने देखा ही नहीं है। लेकिन जो जवाब मिला है उससे मैं जानना चाहूंगा कि रक्षा विभाग के कामकाज को देखने के लिए जो उनका इंजीनियरिंग सर्विस है, एम०ई०एस० है वह काफी अच्छे ढंग से काम कर रहा है इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जो काम बाजार से या खुले मार्केट से सस्ती कीमत, सस्ते दामों में किया जा सकता है उन कामों के लिए एम० ई० एस० का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज एम०ई०एस० ने जिस टैक्नोलाजी को ऐडाप्ट किया है दामों को कम करने के लिए, जिसमें आपने प्री

फैब का जिक्र किया है, वह सीमित जगहों के लिए किया है, जैसे छत के लिए और फ्लोरिंग के लिए जब कि प्री फैब टैक्नालाजी जिसका पूरी दुनिया में जो परंपरागत काम के तरीके हैं उनसे उनकी कीमत करीब-करीब 40 प्रतिशत कम पड़ रही है। हिन्दुस्तान में भी कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप पूरा का पूरा ऐसा तरीका क्यों नहीं निकालते हैं जिससे प्री फैब का इस्तेमाल करके दामों को कम किया जा सकता है?

इसी सवाल के खंड बी में एक और बात आपसे जानना चाहूंगा कि आप यह बताने की कृपा करें कि जो ऐसी जगहों पर जहां पर कि जैसे आप हास्पिटल बना रहे हैं, रक्षा के सैन्य सामग्री के लिए मकान बना रहे हैं, उन जगहों पर आप क्यों नहीं खुले बाजार में इसका एक ओपन टेंडर करके इस बात के लिए लोगों को जागृत करते हैं कि सस्ती टैक्नालाजी का इस्तेमाल करके दामों को कम किया जा सके?

SHRI MALLIKARJUN: Sir, as I have already mentioned in the Statement, we are certainly using the prefabricated system also. Apart from that, to reduce the cost of construction on the civil side and in the marine construction also, we have to be regularly and constantly in touch with research institutes like the Central Building Research Institute, the National Building Organisation, the Central Road Research Institute etc. We certainly use the prefabricated technology, which has been mentioned by the hon. Member.

श्री दिग्विजय सिंह: सभापति महोदय, मेरे पहले सवाल का ही जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि प्री फैब जिसका जिक्र मंत्री जी ने किया है, उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल आप टैक्नालाजी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे दामों को कम किया जा सके। उसका जवाब तो मुझे मिला नहीं। अगर उसका जवाब मिले तो मैं दूसरा सप्लीमेंटरी पूछ।

MR. CHAIRMAN: He said he is using it.

SHRI MALLIKARJUN: We are using it.

SHRI DIGVIJAY SINGH: He said they are using it partly.

SHRI MALLIKARJUN: The hon. Member wants the entire construction to be of prefabricated technology. It is not possible. It depends on various factors and also on location.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Sir, I need your protection because I did not get a reply to my first Supplementary.

MR. CHARMAN: I think he has answered it.

SHRI DIGVIJAY SINGH: No, Sir,

सभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने जिक्र किया कि तमाम वेरियस आर्गनाइजेशंस जिनका नाम उन्होंने लिया कि इन आर्गनाइजेशनों के माध्यम से वह दामों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एम०बी०ओ० का, सी०आर०आर०आई० का, एस०ई०आर० सी० का, हुडको का नाम लिया। लेकिन मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक संगठन सरकार की तरफ से बनाया गया है बी.एम०पी०टी०सी०, यह सरकार का एक ऐसा संगठन है जिसमें सारे मंत्रालय करीब-करीब हिस्सेदार हैं। आपका विभाग रक्षा मंत्रालय इसका हिस्सेदार नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज तक आप इसके हिस्सेदार क्यों नहीं बन पाये? अगर बनने की इच्छा आप रखते हैं तो इस आर्गेनाइजेशन के सदस्य क्यों नहीं बन पाये? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसमें जो हुडको है, सी०बी०डब्ल्यू०डी० है, ऐसे संगठनों की राय से आप ऐसी कोई नीति बनायेंगे जिससे आपके दाम जो काम करने के लिए निर्धारित हैं उसको कम किया जा सके?

SHRI MALLIKARJUN: Mr. Chairman, Sir, as I have already informed the august House, we are in touch with these re-

search organisations, including HUDCO. The hon. Member wanted to know whether we are a member of the BMPTC organisation. We will consider becoming a member of that organisation. When we are aspiring to construct buildings with low cost material, with recent designs and technology, there is nothing wrong, if I examine the possibility of becoming a member of this organisation.

श्री राम गोपाल यादव : माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के जवाब में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने कुछ कास्ट सेविंग, टाइम सेविंग डिवाइसेस का प्रयोग किया है सशस्त्र बलों द्वारा सिविल/समुद्री निर्माण कार्यों में। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर प्रभावी ढंग से इन उपायों का प्रयोग किया गया है तो पिछले वित्तीय वर्ष में कितना धन विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्य के लिए आवंटित किया था, कितनी योजनाएं ऐसी हैं, निर्माण कार्य ऐसे हैं जो टाइम सेविंग डिवाइस के कारण समय से पहले निर्मित हो गई हैं और उससे कितने धन की बचत हुई है?

SHRI MALLIKARJUN: There are 3353 ongoing projects on hand. Our annual budget varies from Rs. 450 crores to Rs. 500 crores. So far as our present budget is concerned, it is Rs. 454 crores. After adopting the advanced technology innovation on the construction side, we are going to save Rs. 40 to Rs. 45 crores; otherwise the budget would have been nearly Rs. 500 crores.

DR. NAUNIHAL SINGH: Mr. Chairman, Sir, will the hon. Prime Minister or the hon. Minister in the Ministry of Defence enlighten this House whether Generals at various levels have no less than 144 security officers attached to them at their residences? A colossal expenditure is involved in maintaining their bungalows, when the Government is more interested in cutting down the expenditure.

MR. CHAIRMAN: I am afraid that has nothing to do with the question.

DR. NAUNIHAL SINGH: Cost is involved.

MR. CHAIRMAN: It is about construction. Please ask a relevant question.

DR. NAUNIHAL SINGH: In the construction of bungalows and for their maintenance, colossal expenditure is involved, when the nation is demanding the cutting down of Government expenditure.

MR. CHAIRMAN: Does the Minister want to answer that?

SHRI MALLIKARJUN: A portion of the hon. Member's question relates to maintenance of bungalows. MES in taking all adequate measures for maintaining all the assets in terms of bungalows or whatever it is. Maintenance does not merely include repairs to certain areas of the bungalows but also providing electricity, water, payment of taxes and so on and so forth. We are very conscious of all that. There are certain laid down procedures which we are following.

श्री अजीत जोगी : सभापति जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में विस्तार से बताया है कि एम०ई०एस० एकोनोमी करने के लिए क्या-क्या उपाय कर रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आम धारणा और सार्वजनिक मान्यता है कि एम०ई० एस० जिस मूल्य पर काम करती है... वैसा ही काम यदि दूसरी कोई सिविल कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट एजेन्सी करती है, जैसे स्टेट पी०डब्ल्यू०डी० या सी०पी० डब्ल्यू०डी० या जो दूसरी कार्पोरेशन कंस्ट्रक्शन के लिए बनी हुई है, तो उनकी कास्ट आफ कंस्ट्रक्शन एम०ई०एस० की अपेक्षा कम आती है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है जिससे पता चल सके कि वैसे ही कंस्ट्रक्शन के लिए एम० ई०एस० कितना खर्च करता है और दूसरे जो स्टेट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की एजेन्सी करता है तो वह कितना खर्च आता है? यदि स्टेट या सेन्ट्रल गवर्नमेंट की एजेन्सी के काम करने में कम खर्च

आता है तो उसको तुलना में एम.ई. एस. द्वारा कहां पर ज्यादा खर्च हो रहा है और उसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? मेरे सवाल का (ब) हिस्सा यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि अब जब कि गोपनीयता का इतना महत्व निर्माण कार्यों में, सिविल निर्माण कार्यों में, नहीं रह गया है तो एम.ई.एस. के ढांचे में जो इतना अधिक व्यय हो रहा है उसको... **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: You have asked the question already. Please sit down. I would ask the Minister to reply.

श्री अजीत जोगी : उसको कम करने पर आप विचार करेंगे और एम.ई. एस. के ढांचे को समाप्त करके धीरे-धीरे यह काम निजी जो कंस्ट्रक्शन कम्पनियां हैं उनको सौंपा जाने लगे?

SHRI VISHVJIT P. SINGH: That is why the buildings of the MES are standing even after so many years and the buildings of the CPWD collapse.... (*Interruption*)... I am not the Minister, but .... (*Interruption*).

SHRI MALLIKARJUN: There is no question of scrapping the Military Engineering Services and adopting the other things which have been suggested by the hon. Member.

Sir, so far as the estimates are concerned, normally, whether it is the CPWD or the MES, we take the estimates on the basis of the prices of material which are required and so on and so forth. For example, for one square foot of plinth area, we normally take Rs. 225—250/-. It will be almost similar with the other organisations because the cost of material will not change whether it is the CPWD or the MES. It is a question of management, it is a question of supervision, it is a question of dedication of the concerned engineers to take up the object of completing the project in time.

श्री सच्चिदानन्द : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से रक्षा और प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कारवार में भी बरड प्रोजेक्ट है, जिसका शिलान्यास राजीव गांधी जी ने किया था उसको जो मोडर्न टेक्नोलोजी के आधार पर बनाया जा रहा है, वहां अग्निशामक यंत्रों की जो स्थापना की जाएगी उसमें भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस योजना के लिए इस वर्ष कितना धन दिया गया है और यह योजना कब तक पूरी होगी।

SHRI MALLIKARJUN: Sir, we are seriously considering the sea-bird project and we are certainly using all the modern technology and other necessary infrastructure to complete it as early as possible and according to the funds available at our disposal.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : माननीय सभापति महोदय, एक तरफ सेना के निर्माण कार्यों में मितव्ययिता की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सेना के निर्माण कार्यों में किये गये धन की बर्बादी की ओर मैं प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मैं सी.ए.जी. की रिपोर्ट देख रही थी, सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट में बताया है और कई उदाहरण देकर बताया है कि किस तरह से सेना के निर्माण कार्यों में धन की बर्बादी हो रही है। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नेवल एयर स्टेशन के 99 करोड़ के प्रकल्प के निर्माण में हुई अव्यवस्था के चलते सेना को करोड़ों रुपयों का नुक्सान हुआ और उसके साथ ही सिविल वर्क के सेक्शन में हुई देरी के कारण 32 करोड़ रुपये के हवाई जहाजों का वर्षों तक इस्तेमाल नहीं किया जा सका जिसके चलते सेना को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और उसके साथ ही मार्च, 1993 तक पूरे हो जाने वाले 69 प्रकल्प थे, उनमें से 68 को टाइम का एक्सटेंशन दिया गया जिसके चलते सेना को करोड़ों रुपये का नुक्सान हुआ। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक तरफ हम मितव्ययिता की बात करते हैं दूसरी तरफ हमारी सेना के

निर्माण कार्यों में इस तरह की धांधली चल रही है तो हमारे देश के सीमित साधनों को देखते हुए हमारे प्रतिरक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अव्यवस्था का बोलबाला है, उस भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को खत्म करने के लिए हमारे प्रधान मंत्री क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

MR. CHAIRMAN: Please conclude the question. You have asked it. (*Interruptions*) Don't repeat it. Please conclude.

SHRI MALLIKARJUN: Sir, in regar to what the hon. Member has mentioned, if she has got any specific instance, she can write to me. (*Interruptions*) we will look into the matter.

SHRI DIPEN GHOSH: She is refering to the SAG report. (*Interruptions*)

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, she is quotin from the CAG report. (*Interruptions*)

SHRI MD. SALIM: Sir, she has cited a specific instance.

MR. CHAIRMAN: Will the Minister answer?

SHRI MALLIKARJUN: Sir, so far as the CAG report is concerned, I don't have to say anything in this august House. It will be placed before the Public Accounts Committee and whatever findings the Public Accounts Committee give, will be communicated to the Defence Ministry.

Implementation of the recommendations of the Arrears Committee

*243. SHRI J. S. RAJU:
SHRI V. GOPALSAMY:†

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 479 given in the Rajya Sabha on the 29th April, 1993 and state:

(a) what are the recommendations of the Arrears Committee implemented by Government so far;

(b) what steps have been taken to implement all the recommendations and the progress made thereof since the constitution of the working groups in October, 1992;

(c) whether Government have sought the opinion of the Law Commission on the above report, if so, the opinion given thereon;

(d) what is the sonctioned strength of judges in each High Court and the actual strength thereof as on date; and

(e) whether Government propose to increase the strength of judges in each High Court, if so, by when this increase is likely to be made effective?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The recommendations made by the Arrears Committee covering various aspects, have been commended to all the concerned Central Ministries, State Governments and High Courts for necessary follow-up action. Some of the recommendations viz; relating to raising of the pecuniary jurisdicition of District Courts, introduction of a Centrally Sponsored Scheme to upgrade infrastructural facilities for the judiciary setting up of training facilities for legislative drafting decision to set up an All India Training Academy etc., have already been implemented by the concerned authorities. No reference has been made to the Law Commissson. However, as per the decision taken in the Law Ministers Conference held in October, 1992 at Bangalore, working groups of State Law Ministers have been constituted to suggest further measures for the implementation of the recommendations of the Arrears Committee so as to expedite the disposal of pending cases in the Courts.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri V. Gopalsamy.